

**वर्तमान संदर्भ में उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा**

डॉ० पुष्पा देवी सेठ, Associate Prof. Deptt. of Education Sampurnanand Sanskrit University,
Varanasi

डॉ० विद्याबाबा भुक्ला, Assistant Prof. Deptt. of Education Sampurnanand Sanskrit University,
Varanasi

Abstract

शिक्षा भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमीर व गरीब के मध्य बढ़ती दूरी, युवा वर्ग से उनके माता पिता की बढ़ती अपेक्षाएँ, भौगोलिक अंतर अत्यधिक है, साथ ही सामाजिक विभिन्नताएँ और शिक्षा में असमानता भी गम्भीर समस्या है। इन समस्याओं को संदर्भ में लेते हुए इस पंचवर्षीय योजना (2012-17) में केन्द्र सरकार ने शिक्षा में श्रेष्ठता, समानता और प्रसार पर जोर दिया है। प्रस्तुत प्रपत्र में भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत करते हुए भविष्य का मार्ग प्रस्तुत किया गया है।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com 4.194, 2013 SJIF©
SRJIS2014

देश में स्थायी प्रगति व उन्नति के लिए आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समानता अति आवश्यक है। समाजवादी समाज ही भ्रष्टाचार से मुक्त वैज्ञानिक दृष्टि वाले परिपक्व समाज की रचना को प्रेरित कर सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व समाज सुधारकों, स्वामी विवेकानन्द दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी ने इस दिशा में प्रयास किये इनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही ज्ञान का द्वार खोल सकती है, सामाजिक परिवर्तनों का मार्ग प्रस्तुत कर सकती है। डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि— “भारत के प्रत्येक बच्चों को एसी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिले जिसका उपयोग वह व्यावहारिक जीवन में कर सके। इसी

तरह उच्च शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख अस्त्र बन सकती है। उच्च शिक्षा वैज्ञानिक सोच वाले आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में सहायक हो सकती है।

वस्तुतः उच्च शिक्षा विविष्ट ज्ञान की पुष्टी करती है। नये ज्ञान का सृजन करती है व समाज को नयी दिशाओं में ले जाने व प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। उच्च शिक्षा मात्र ज्ञान के प्रसार का माध्यम नहीं होनी चाहिए, वरन् भोध व अनुसंधान द्वारा नये ज्ञान सृजन, विद्यमान ज्ञान के नये-नये उपयोग, समाज की सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण

के उपाय बताने में समर्थ होनी चाहिए। तब ही उच्च शिक्षा प्रगति व सम्पन्नता का वाहक बन सकती है। किंतु क्या भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इस पर विचार करना होगा। दरअसल भारत में शिक्षा सरकार का दायित्व समझी जाती है। सस्ती सुलभ व गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक से उच्च शिक्षा की व्यवस्था राज्य का दायित्व समझी जाती है।

हालांकि इसी देश में प्राचीन काल में शिक्षा स्वायत्त रही है। किंतु अंग्रेजी भाषा के दौरान शिक्षा पूर्णतः राज्याश्रित हो गयी। जबकि आदर्श रूप में शिक्षा स्वायत्त और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। जिससे समाज की सेवा आकांक्षाओं के अनुरूप इसे ढाला जा सके। लेकिन सरकारी नियंत्रण व वित्तपोषणवाली शिक्षा मात्र निर्देहात्मक बन जाती है और राजकीय व्यवस्था की सारी कमियाँ उसमें समाहित हो जाती है। यही कारण है कि राज्याश्रित शिक्षा व्यवस्था वित्तीय संसाधनों के अभावों से जूझते हुए चल रही है और इसमें नये प्रयोग, नवाचार, राज्य निर्देशित है।

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक कमियों एवं व्याधियों से युक्त है। आज यदि देश के 200 केन्द्रीय विविद्यालयों, आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया जाय, तो संपूर्ण उच्च शिक्षा ही अर्धचेतनावस्था में है। भौक्षिक सुधारों में कोई प्रगति नहीं है। शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में भारी अंतर है। शिक्षा में समाज की भागीदारी न्यूनतम रूप में है, ऐसे में शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, यह एक विचारणीय बिन्दु है। जबकि वैश्विक भौक्षिक प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण भागीदार बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था अपरिहार्य है। वस्तुतः समृद्ध देशों की सफलता का एक बड़ा कारण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर, मलेेशिया, हांगकांग, आस्ट्रेलिया आदि देशों की आर्थिक उन्नति उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा के ही कारण है। हालांकि स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय शिक्षा क्षेत्र में मात्रात्मक या संख्यात्मक प्रगति काफी हुई है। शिक्षा से भौतिक समृद्धि का पक्ष अनेक क्षेत्रों में दृश्य है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सिद्धान्तहीन भौक्षिक अवधारणा और उद्देश्यहीन दिशा की दृष्टि से उच्च शिक्षा की दृश्य

चुनौतियों है। उच्च शिक्षा की खेती का उत्तरदायी उत्पादन जारी है। आज हमारे देश में 16 आई.आई.टी. , 30 एन.आई.टी. , 359 महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान एवं हजारों इंजीनियरिंग संस्थान हैं। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप दो सौ विविद्यालयों में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। जबकि कुछ दशक पूर्व भारत और चीन शिक्षा के क्षेत्र में समान थे। किंतु आज उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत चीन से पिछड़ चुका है। गत 20 वर्षों में चीन के बीजिंग, सिंहुआ, भांघाई, जिओटांग, भूडान आदि के विविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं। जिनकी विश्व रैंकिंग है। यह सर्वविदित है कि आर्थिक सर्वश्रेष्ठता बेहतर तकनीकी शिक्षा, भोध और विकास पर निर्भर है। किंतु भोध और विज्ञान क्षेत्र में पेटेंट मामले में भारत में कोई उत्तरोत्तर विकास नहीं दिखता।

यहाँ 400 विविद्यालय एवं डीम्ड विविद्यालय हैं किन्तु यहाँ मात्र प्रति वर्ष 5 हजार छात्र ही भोध कर पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करते हैं। जबकि अमेरिका, चीन में क्रमशः 25 हजार एवं 35 हजार छात्र प्रतिवर्ष पीएचडी करते हैं। आज भारत को 538 विविद्यालय एवं 26,478 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 160 करोड़ छात्रों का वैश्विक औसत मात्र 12 प्रतिशत है। हालांकि केन्द्र सरकार वर्ष 2020 तक इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। लेकिन उल्लेखनीय है कि गत दशकों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर खुले निजी शिक्षण संस्थान मानकहीन एवं स्तरहीन हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भारत में 153 विविद्यालयों एवं 9875 महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात, वित्तीय अनुदान, कमरे प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के बुनियादी संकटों पर चिंता व्यक्त की थी। उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा में भी खामियां हैं। उच्च शिक्षा को संचालित करने के लिए यूजीसी है। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा को अखिलभारतीय तकनीकी शिक्षा परिशद एआइसीटीई संचालित करती है। यद्यपि देश में तकनीकी संस्थान तो बहुत हैं लेकिन अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की भारी कमी है। फलतः इंजीनियरिंग करके भी छात्र 20 हजार की अदद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इस समय देश के 13 हजार तकनीकी संस्थानों से छात्र इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल में ही गठित नई सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्किल इंडिया' की बात कही है। यानि हर छात्र तकनीकी, विज्ञान के माध्यम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करें। साथ ही प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण व्यवस्था हो, कि भारत विश्व को उत्तम शिक्षक दे सकें। इसके लिए भारत के पास मानवीय भाक्ति भले ही अधिक हो, किन्तु संसाधनों की भारी कमी है। वर्ष 2020 तक 5 करोड़ छात्रों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता होगी। अभी शिक्षा क्षेत्र में देश के बजट का साढ़े तीन फिसदी ही खर्च होता है। जिसे बढ़ाकर 8 फिसदी करने की मांग है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय

संसाधन जुटाने के साथ ही शिक्षा एवं बोध स्तर को भी उँचा उठाना होगा। अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए डिस्टेंस व ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था। आज 250 से अधिक दूरस्थ शिक्षण संस्थान के माध्यम से 40 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह दूरस्थ शिक्षा के द्वारा 22 फिसदी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सन् 1982 में हैदराबाद में बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एवं सन् 1985 में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बनी। वर्ष 2010 में माधव मेनन कमेटी ने दूरस्थ शिक्षा अधिकारों व कार्यों पर टिप्पणी की, फलतः मई 2013 में दूरस्थ शिक्षा परिशद को भंग कर यूजीसी में अलग से डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बना दिया गया। इसके साथ ही दस शिक्षकों एवं आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षण संस्थाओं का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन ढांचा एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की कमी को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) प्रारंभ किया गया है। स्वतंत्रता पचास उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुधार क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को पहला बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इसके अर्न्तगत सभी प्रदेशों से राज्य, उच्च शिक्षा परिशद गठित करने और राज्य उच्च शिक्षा आयोग बनाने को कहा गया है। इसी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 22,853 हजार करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। यह अभियान केन्द्र और राज्यों के बीच 65:35 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर आगे बढ़ाया जायेगा। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में इसके प्रबंधन, निगरानी, बोध, मूल्यांकन की तैयारी के लिए 2.24 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के लिए उच्च शिक्षा में ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वायत्ता, विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, विविधता और विश्वदृष्टि जैसे मूल्यों पर आधारित हो। साथ ही छात्रों को ऐसी वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा-ज्ञान मिले जो व्यावहारिक एवं रोजगारपरक हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संपादकीय – अतुल कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय संकल्पना, अ0भा0वि0 दिल्ली, 2003 पृ0 41
संपादकीय – अतुल कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय संकल्पना, अ0भा0वि0 दिल्ली, 2003 पृ0 31
दैनिक जागरण, संपादकीय 15 अप्रैल 2013
अमर उजाला, संपादकीय 7 फरवरी 2014
दैनिक जागरण, 9 मार्च 2013
संपादकीय, सिंह माया इंकर अध्यापक शिक्षा
असमंजस में, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली 2007, पृ0 157